

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 जनवरी 2017—पौष 14, शक 1938

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2017

क्रमांक : 1-08-2010-साठ – मंत्रि परिषद दिनांक 02 दिसम्बर 2016 को सम्पन्न बैठक में मध्य प्रदेश बायोमास आधारित विद्युत (पावर) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नीति, 2011 में प्रावधान, अंतर्निहित किया जाना अनुमोदित किया गया है। सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उक्त का प्रकाशन "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनु श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.

- a) कण्डिका-1 शीर्ष - "प्रस्तावना" में नवीन उप-कंडिका 1.4 के रूप में निम्न जोड़ा जावे -

"नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिभाषित सभी "बायोमास" से विद्युत उत्पादन इस नीति में मान्य होंगे। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा किसी विशिष्ट बायोमास से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक पृथक व उच्च टैरिफ दर का निर्धारण किये जाने की स्थिति में और परियोजना द्वारा म. प. पावर मैनेजमेंट कम्पनी को आयोग द्वारा निर्धारित दर पर विद्युत विक्रय किये जाने पर, परियोजना को उच्च दर का लाभ तभी मिलेगा, यदि परियोजना द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु मात्र इस विशिष्ट बायोमास का उपयोग किया जा रहा हो।

- b) कण्डिका-1 शीर्ष - "प्रस्तावना" में नवीन उप-कंडिका 1.5 के रूप में निम्न जोड़ा जावे -

"इस नीति से बायोमास आधारित को-जेनरेशन परियोजनाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।"

- c) कण्डिका-2 शीर्ष - "पंजीकरण के लिए मापदंड" में उप-कंडिका 2.1 में "25 किलोमीटर त्रिज्या क्षेत्रफल" के पूर्व निम्न जोड़ा जावे -

"(भौगोलिक क्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर) यथासम्भव।"

- d) कण्डिका-2 शीर्ष - "पंजीकरण के लिए मापदंड" में उप-कंडिका 2.2 अंत में निम्न जोड़ा जावे-

"तथापि किसी उद्योग के बायोमास अवशेष पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के सन्यंत्र में उपलब्ध बायोमास पर निर्भरता व 15 मेगावाट से अतिशेष उत्पादित विद्युत का केप्टिव उपयोग होने की स्थिति में, 15 मेगावाट क्षमता सीमा बंधन लागू नहीं होगा।"

- e) "पंजीकरण के लिए मापदंड" में उप-कंडिका 2.3 के अंत में निम्न जोड़ा जावे -

"15 मेगावाट से अधिक क्षमता की विद्युत परियोजनाओं के लिए निर्धारित अधिकतम पारम्परिक ईंधन वह होगा, जो 15 मेगावाट क्षमता की परियोजना के लिए निर्धारित है।"

- f) कण्डिका-2 शीर्ष - "पंजीकरण के लिए मानदण्ड" के अंतर्गत नवीन उपकंडिका 2.7 के रूप में निम्न जोड़ा जाए- "बायोमास आधारित विद्युत व को-जनेरेशन परियोजनायें, यदि वे उस उद्योग से सहमति प्रस्तुत करती हैं, जिस पर वे आधारित हैं, कभी भी परियोजना आवंटन हेतु आवेदन कर सकती हैं। ऐसा आवेदन तभी अनुमोदित किया जाएगा, यदि प्रस्तावित परियोजना किसी स्थापित/स्थापनाधीन परियोजना के लिए निर्धारित 25 किलोमीटर के सुरक्षित क्षेत्रफल में प्रस्तावित नहीं है और, यदि है, तब स्थापित/स्थापनाधीन परियोजना की बायोमास एसेसमेंट रिपोर्ट में इस उद्योग से उपलब्ध बायोमास शामिल नहीं है। इस श्रेणी की सभी परियोजनाओं को कंडिका 2.1 अंतर्गत, 25 किलोमीटर त्रिज्या क्षेत्रफल में अन्य परियोजना की स्थापना वार्जित होने का लाभ प्राप्त नहीं होगा, परंतु नीति अंतर्गत अन्य सभी लाभ प्राप्त होंगे। ऐसी परियोजना आगामी RfP में नियमित रूप से आवेदन प्रस्तुत कर पात्र पाए जाने पर अधिकतम निशुल्क ऊर्जा बोली के आधार पर कंडिका 2.1 का लाभ उठा सकेगी।"

मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.